(c) the action Government propose to take in the matter in the context of the above findings of experts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): fa) Blue Asbestos is neither produced nor imported in India as it is only available in South Africa. Asbestos Information Centre, New Delhi informed that use of Blue Asbestos has been prohibited by ILO and WHO. *The* import of Asbestos is cancalised through MMTC.

(b) Since Blue Asbestos is not being im ported or produced it was not considered necessary for banning.

(c) However, in consultation with DGTD it is proposed to bring Blue Asbestos i.e. Crocid:lite under Annexure 2-A in Import & Export Policy 1990—93.

**नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन**

2158. **कुमारी सईदा खातून** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उद्योग-पतियों, श्रमिक नेताओं, सांसदों, विधायकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के सुझाव आमंत्रित किए हैं या आमंत्रित करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या संगठित श्रमिक वर्ग ने इस नीति का विरोध किया है, यदि हां, तो इनके द्वारा क्या-क्या कारण बताए गए हैं ; और

(ग) इस औद्योगिक नीति के परि-णामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन)** : (क) लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना और कार्य-विधियों को सरल और कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है सांसदों, विधायकों, उद्योग-पतियों, श्रमिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों के सुझावों का हमेशा स्वागत है ।

(ख) कुछ ट्रेड यूनियन के संगठनों में 29 नवम्बर, 1991 को औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया था जिनकी मांग थी कि ट्रेड यूनियनों से परामर्श करके सरकार वित्तीय और औद्योगिक नीतियों को फिर से तैयार करे सार्वजनिक सरकारी एककों इत्यादि निजीकरण को रोकने के उपाय किए जा सकें । सरकार ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है जो श्रमिकों और अन्य सम्बद्ध मामलों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करेगी और उपयुक्त सिफारिशें देगी ।

(ग) नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के पश्चात् 31-10-1991 तक 250 से अधिक विदेशी सहयोग प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है इनमें से 60 से अधिक प्रस्तावों में लगभग 170 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परि-कल्पना की गई है ।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार की शिकायतें**

2159. **श्री रणजीत सिंह :**
**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक औद्योगिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों, पदोन्नतियों और गबन से संबंधित अनेक शिकायतें बिना जांच किए लम्बित पड़ी हैं ; यदि हां, तो मार्च, 1991 तक ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन शिकायतों में से कितनी-कितनी शिकायतें गबन, भ्रष्टाचार, पदो-न्नतियों और नियुक्तियों से संबंधित हैं तथा वे कितने-कितने समय से लंबित हैं ?